सत्यमेव जयते

रोज़गार समाचार

www.rojgarsamachar.gov.in
www.employmentnews.gov.in

साप्ताहिक

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
(वार्षिक शुल्क : ₹ 350)

खण्ड 37 अंक 44 पृष्ठ 40 | नई दिल्ली 2-8 फरवरी 2013 | ₹ 8.00

जम्मू-कश्मीर पर एक नज़र

उड़ानः युवाओं के लिए रोज़गार के सुनहरे क्षितिज

— प्रिसिल्ला विन्सेंट

इस अंक से हम जम्मू-कश्मीर में रोज़गार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला ने एक विशेष संदेश भेजा है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि ''राज्य को उग्रवादी और विघटनकारी शक्तियों का बुरी तरह से सामना करना पड़ा है। इन स्थितियों के साथ ही क्षेत्रीय असंतुलन भी हैं, जो भारत जैसे बड़े और विविधताओं वाले देश में होना अवश्यंभावी हैं। नतीजतन राज्य में समग्र स्थिति ऐसी बनी है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के अब तक दोहन न किए गए विकास के क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी का अभाव है। देश के विकास मार्ग में सबसे बड़ी कमी यह रही है कि उसमें युवाओं की भागीदारी का स्पष्ट रूप से अभाव रहा है. इसकी वजह युवाओं में कौशल की कमी कही जा सकती है। इस कमी को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि एक ऐसा बौद्धिक और व्यावहारिक मंच तैयार किया जाए जिससे उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिले, जहां कौशल की कमी है और कौशल के आधार में सुधार के लिए जिसे लक्ष्य बनाया जा सके। इस बारे में मुझे यह जानकर खुशी हुई कि रोज़गार समाचार, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में रोज़गार के अवसरों की संभावनाओं के बारे में एक शृंखला शुरू की जा रही है।''

उड़ान एक बेजोड़ परियोजना है, जिसमें कंपनियों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और जम्मू-कश्मीर के युवाओं की भागीदारी है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य पांच वर्ष की अवधि में जम्मू कश्मीर के 40,000 युवाओं तक पहुंचना है. समूचे भारत की कंपनियां तीन से नौ महीने की आदर्श अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के बारे में एनएसडीसी के साथ अनुबंध करेंगी, जो जम्मू-कश्मीर के स्नातकों और स्नातकोत्तर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए दाखिला देगा और रोज़गार प्राप्त करने में मदद करेगा.

उड़ान के लक्ष्य

- जम्मू-कश्मीर के युवाओं को देश की जानी मानी और सुस्थापित कंपनियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें भारतीय कॉरपोरेट जगत से परिचित कराया जाएगा.
- जम्मू कश्मीर के प्रशिक्षित युवाओं को अच्छे वेतन के साथ रोज़गार प्रदान किया जाएगा.
- भारतीय कारपोरेट क्षेत्र का परिचय जम्मू-कश्मीर में उपलब्ध समृद्ध प्रतिभा पूल से कराया जाएगा.
- देशभर के संगठनों को एकजुट किया जाएगा ताकि वे जम्मू-कश्मीर से प्रतिभाशाली उम्मीदवारों का चयन कर सकें, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करें और या तो अपने संगठन में या उससे बाहर रोज़गार दिलाएं अथवा स्व-उद्यमी बनने में उन्हें सक्षम बनाएं.

राज्य में व्यापक प्रतिभा पूल उपलब्ध है. निम्नांकित तालिका से स्पष्ट होता है कि जम्मू-कश्मीर में विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में कितनी बेरोजगारी है.

जम्मू-कश्मीर में प्रतिभा पूल

स्नातक (दिसंबर 2011 में बेरोज़गार)					स्नातकोत्तर (दिसंबर 2011 में बेरोज़गार)				
कला	विज्ञान	वाणिज्य	अन्य	कुल	कला	विज्ञान	वाणिज्य	अन्य	कुल
38891	21859	5440	19356	85546	10258	5446	1502	4008	21214

इंजीनियरी स्नातक (दिसंबर 2011 में बेरोजगारी)

सिविल	इलेक्ट्रिकल	टी/कोम	मैक	हाइड्रोलिक	रसायन विज्ञान	खनन
1018	1142	757	936	14	20	5
एरोनोटिक्स	**प्रोडक्शन**	**एयरक्राफ्ट**	**मैट्रोलॉजी**	**आटोमोबा.**	**एमसीए**	**कुल**
5	13	2	70	113	1277	5370

आठ कंपनियों (गोदरेज की भागीदारी के साथ सीआईआई), टीसीएस, विप्रो (बीपीओ), एचसीएल इन्फोसिस्ट्म्स, फ्यूचर ग्रुप, इन्फोसिस, येस बैंक और एचसीएल टेक्नोलॉजी) और एक प्रशिक्षण संस्थान (भारतीय कौशल विकास संस्थान) ने विभिन्न अन्य कंपनियों की भागीदारी के साथ जम्मू-कश्मीर के 16340 युवाओं को अगले पांच वर्ष के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने और तदनुरूप रोज़गार मुहैया कराने का वायदा किया है. ये कंपनियां विविध प्रकार की शैक्षिक पृष्ठभूमियों वाले उम्मीदवारों का चयन करेंगी.

26 मार्च, 2011 को गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉ. जी. रंगराजन की मौजूदगी में **उड़ान** वेबसाइट का उद्घाटन किया था. **उड़ान** वेबसाइट अत्यंत उच्च तकनीकी प्रणाली है जो सभी सम्बद्ध पक्षों को एक समान मंच पर एकत्र करती है. **उड़ान** की वेबसाइट हैः **http://www.nsdcIndia.org/Udaan/.**

उम्मीदवार : वेबसाइट के जरिए जम्मू-कश्मीर के युवा अधिक संख्या में शामिल किए जाएंगे ताकि वे **उड़ान** के अंतर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण और रोज़गार के अवसर प्राप्त करने के लिए आसानी से आवेदन कर सकें. उम्मीदवार अपने रोज़गार के आवेदन की स्थिति भी ऑन लाइन देख सकते हैं. कंपनियों द्वारा संक्षिप्त सूची में शामिल किए गए उम्मीदवारों को ई-मेल के जरिए अधिसूचित किया जाता है.

शेष पृष्ठ 40 पर

रोज़गार सारांश

सी.सु.ब.

- सीमा सुरक्षा बल को 430 हेड कांस्टेबलों (रेडियो ऑपरेटर) की आवश्यकता.

अंतिम तारीख 28.02.2013

बैंक

- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स द्वारा 77 विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती.

अंतिम तारीख 16.02.2013

दिल्ली पुलिस

- दिल्ली पुलिस द्वारा 522 महिला कांस्टेबल (कार्यकारी) भर्ती की जानी है.

(अंतिम तारीख 01.03.2013)

गन कैरिज फैक्टरी

- गन कैरिज फैक्टरी, जबलपुर को आवश्यकता है 255 लोहार, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मिलर, टर्नर आदि की.

बैंकों, सशस्त्र बलों, रेलवे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सरकारी विभागों में अन्य रिक्तियों के लिए अंदर के पृष्ठ देखें.

जानिए अपना बजट

केंद्रीय बजट : आय व्यय का ताना-बाना

— हैप्पी पंत

किसी भी सरकार के बजट से अभिप्राय है किसी वर्ष विशेष के लिए व्यय और प्राप्तियों का व्यापक विवरण. यह आगामी वर्ष के लिए व्यय और उन व्ययों को पूरा करने के लिए प्राप्तियों के बारे में सरकार की योजनाओं की अभिव्यक्ति है.

भारत में केंद्रीय बजट दस्तावेज के एक सेट के जरिए संसद में (आमतौर पर हर वर्ष फरवरी के अंतिम कार्यदिवस को) पेश किया जाता है. हमारे देश में बजट से सम्बद्ध प्रमुख धारणाओं को समझने के लिए हम केंद्रीय बजट दस्तावेज में से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी बजट एट ए ग्लैंस यानी बजट एक नज़र में का अध्ययन कर सकते हैं. केंद्रीय बजट 2012-13 को एक मॉडल के रूप में देखा जा सकता है.

केंद्रीय बजट 2012-13: बजट एक नज़र में
(आंकड़े करोड़ रुपये में)

		2010-11 वास्तविक	2011-12 बजट अनुमान	2011-12 संशोधित अनुमान	2012-13 बजट अनुमान
1	**राजस्व प्राप्तियां**	**7,88,471**	**7,89,892**	**7,66,989**	**9,35,685**
2	कर राजस्व (केंद्र का निवल)	569869	664457	642252	771071
3.	गैर कर राजस्व	218602	125435	124737	164614
4.	**पूंजी प्राप्तियां (5+6+7)**	**4,08,857**	**4,67,837**	**5,51,730**	**5,55,241**
5.	ऋणों की वसूलियां	12420	15020	14258	11650
6.	अन्य प्राप्तियां	22846	40000	15493	30000
7.	ऋण और अन्य देयताएं	373591	412817	521980	513590
8.	**कुल प्राप्तियां (1+4)**	**11,97,328**	**12,57,729**	**13,18,720**	**14,90,925**
9.	गैर-योजना व्यय	**8,18,299**	**8,16,182**	**8,92,116**	**9,69,900**
10.	राजस्व खाते पर	726491	733558	815740	865596
11.	ब्याज भुगतान	234022	267986	275618	319759
12.	पूंजी खाते में	91808	82624	76376	104304
13.	योजना व्यय	**3,79,029**	**4,41,547**	**4,46,604**	**5,21,025**
14.	राजस्व खाते में	314232	363604	346201	420513

(शेष पृष्ठ 40 पर)

दिल्ली पोस्टल पंजीकरण संख्या डीएल-एसडब्ल्यू 1/4100/2012-14 यू. (सी.)-107/2012-14 पूर्व शुल्क के बिना डाक में डालने की अनुमति आर.एन.आई.28729/76 एन.डी.पी.एस.ओ. नई दिल्ली 2/4.02.2013 (₹ 8) प्रकाशन तिथि : 31.01.2013

उड़ान : युवाओं के लिए ...

पृष्ठ 1 का शेष

कारपोरेट्स: प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराते हुए कंपनियां जम्मू-कश्मीर में उपलब्ध बृहत्तर प्रतिभा पूल तक पहुंच कायम कर सकती हैं. कंपनियां आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का ब्यौरा (व्यक्तिगत, शैक्षिक और योग्यता परवर्ती कार्यानुभव) ऑनलाइन देख सकती हैं और अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए आसानी से उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची तैयार कर सकती हैं. वेबसाइट के जरिए कंपनियां चुने हुए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेज सकती हैं, जिसमें इंटरव्यू का समय, तारीख और स्थान का ब्यौरा दिया गया हो. **उड़ान** के अंतर्गत कंपनियों को अपने कार्यक्रमों की सफलता के बारे में तिमाही रिपोर्ट एनएसडीसी को देनी होगी. इस रिपोर्ट का प्रारूप चूंकि वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा इसलिए कंपनियां आसानी से तिमाही रिपोर्ट भेज सकेंगी.

एनएसडीसी: वेबसाइट संचालक के नाते एनएसडीसी **उड़ान** पर निगरानी रख सकता है और उसके कार्यान्वयन का मूल्यांकन कर सकता है. एनएसडीसी **उड़ान** के अंतर्गत पंजीकृत सभी उम्मीदवारों का ब्यौरा और उनकी स्थिति देख सकता है. कंपनियों द्वारा भेजी गई तिमाही रिपोर्टों तक पहुंच होने के कारण एनएसडीसी **उड़ान** के कार्यान्वयन पर प्रभावकारी ढंग से नियंत्रण करने में सक्षम है.

''शिक्षा, कौशल निर्माण और युवाओं की क्षमताओं में सुधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय है, जिसके जरिए हम नए जम्मू-कश्मीर का निर्माण कर सकते हैं. मैं अकसर कहता हूं कि 'नए जम्मू-कश्मीर' का निर्माण हम सभी का समान लक्ष्य है और यह शांति, खुशहाली और लोगों के सशक्तिकरण का प्रतीक है. मैं चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में सिविल समाज का प्रत्येक वर्ग आगे आए और नए जम्मू-कश्मीर के इस महान निर्माण प्रयास में अपना योगदान करे. इस प्रक्रिया में प्रभावकारी हिस्सेदारी के लिए शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और समुचित रोजगार के अवसरों के जरिए लोगों का सशक्तिकरण करना होगा.'' -

—प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह

उड़ान विश्वविद्यालय/कॉलेज समन्वयकों की सूची (जम्मू)

क्र. सं.	नोडल कॉलेज/ विश्वविद्यालय का नाम (जम्मू)	समन्वयक का नाम
1	जम्मू विश्वविद्यालय (जम्मू के लिए मुख्य समन्वयक विश्वविद्यालय)	प्रोफेसर नीलू रोहमेत्रा, डीन, स्टूडेंट्स प्लेसमेंट, जम्मू विश्वविद्यालय , जम्मू, फोन/फैक्सः 0191-2452827, 2430133 सेलः 09469213474 ई-मेल nrohmetra@yahoo.co.uk; dean_students_placement@jammuuniversity.in
2.	राजकीय डिग्री कॉलेज, डोडा	श्री बाबू लाल ठाकुर, सहायक प्रोफेसर (शिक्षा) 9419273174
3.	राजकीय डिग्री कॉलेज, पुंछ	डॉ. जसबीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर (रसायन विज्ञान) 9419632185, 01965221244 ई-मेलः jasbirsingh@rediffmail.com
4.	राजकीय डिग्री कॉलेज, रामबन	श्री सजाद अहमद, सहायक प्रोफेसर (कम्प्यूटर एप्लीकेशंस) 9906664985 ई-मेलः shahsajad29@yahoo.com
5.	राजकीय डिग्री कॉलेज (ब्वायज़), ऊधमपुर	श्री सुधीर सिंह, सहायक प्रोफेसर (अंग्रेजी), 9419159736, ई-मेलः iqac@gdcudhampur.in joysudhir@yahoo.com
6.	राजकीय डिग्री कॉलेज (ब्वायज़), कठुआ	श्री सुमनेश जसरोटिया, सहायक प्रोफेसर (रसायन विज्ञान), 9419150807, 01992-232315 (निवास) ई-मेलः sumneshjasrotia@rediffmail.com
7.	राजकीय डिग्री कॉलेज, किश्तवाड़	श्री सतीश कुमार, सहायक प्रोफेसर (वनस्पति विज्ञान), 9419970080, ई-मेलः satish.bot@gmail.com
8.	राजकीय डिग्री कॉलेज, राजौरी	डॉ. अब्दुल रउफ़ एसोसिएट प्रोफेसर (गणित), 9419276563 ई-मेलः araouf123@gmail.com

उड़ान विश्वविद्यालय /कॉलेज समन्वयकों की सूची (कश्मीर)

क्र स	नोडल कॉलेज/ विश्वविद्यालय का नाम (जम्मू)	समन्वयक का नाम
1	कश्मीर विश्वविद्यालय (कश्मीर के लिए मुख्य समन्वयक	प्रोफेसर मुसादिक ए. सहाफ़ निदेशक सेंटर फॉर करियर प्लानिंग एंड काउंसलिंग, कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर, 9906523959
2.	अमर सिंह कॉलेज, श्रीनगर	प्रोफेसर ज़हूर अहमद चाट, 9419595057
3.	राजकीय डिग्री कॉलेज, कुलगाम	प्रोफेसर पीरज़ादा मोहम्मद युसुफ9419595057
4.	राजकीय डिग्री कॉलेज, पुलवामा	प्रोफेसर मुश्ताक अली 9419024884
5.	राजकीय डिग्री कॉलेज, शोपियां	प्रोफेसर नज़ीर अहमद चराग 9419047885
6.	राजकीय डिग्री कॉलेज, (ब्वायज़) बारामूला	प्रोफेसर इरशाद अहमद वाणी, 9419032863
7.	राजकीय डिग्री कॉलेज, (ब्वायज़) अनंतनाग	प्रोफेसर मोहम्मद यासीन शाह, 9419040906
8.	राजकीय डिग्री कॉलेज, कुपवाड़ा	प्रोफेसर फारूख अहमद मलिक, 9419036917
9.	राजकीय डिग्री कॉलेज, बांदीपोर	प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ पीर, 941904471
10.	राजकीय डिग्री कॉलेज, गंदरबल	प्रोफेसर रोशनआरा, 9419089615
11.	राजकीय डिग्री कॉलेज, बडगाम	प्रोफेसर ज़हीरुद्दीन, 9906619756

(लेखक राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से सम्बद्ध हैं. ई-मेलः **priscilla.vincent@nsdcindia.org**).

केंद्रीय बजट...

पृष्ठ 1 का शेष

15.	पूंजी खाते में	64797	77943	80404	100512
16.	**कुल राजस्व (9+13)**	**11,97,328**	**12,57,729**	**13,18,720**	**14,90,925**
17.	राजस्व व्यय	1040723	1097162	1161940	1286109
18.	पूंजी व्यय	156605	160567	156780	204816
19.	**राजस्व घाटा (17-1)**	**2,52,252**	**3,07,270**	**3,94,951**	**3,50,424**
20.	**राजकोषीय घाटा (16-(1+5+6)**	**3,73,591**	**4,12,817**	**5,21,980**	**5,13,590**
21.	**प्राथमिक घाटा (20-11)**	**1,39,569**	**1,44,831**	**2,46,362**	**1,93,831**

स्रोतः केंद्रीय बजट 2012-13, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार.

जैसा कि 'बजट एक नजर में' तालिका के अंतर्गत दर्शाया गया है, इसमें केंद्रीय बजट के व्यय भाग और प्राप्ति भाग दोनों का सारांश दिया गया है और प्राप्ति भाग में ऋण (जो सम्बद्ध वर्ष के राजकोषीय घाटे को कवर करने के लिए आवश्यक होते हैं) भी दर्शाए गए हैं.

हम इनके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और व्यय एवं प्राप्तियों के बारे में अन्य महत्वपूर्ण धारणाओं को निम्नांकित रूप में समझ सकते हैं.

सरकारी प्राप्तियों का वर्गीकरण

पूंजी प्राप्तियां – इनमें वे प्राप्तियां शामिल हैं जिनकी परिणति सरकार की आस्तियों में कमी अथवा सरकार की देयताओं में बढ़ोतरी के रूप में होती है.

– **'आस्तियों में कमी'** के कारण पूंजी प्राप्तियां: सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूलियों और विनिवेश से प्राप्त आय.

-देयताओं में बढ़ोतरी के कारण पूंजी प्राप्तियां: ऋण.

राजस्व प्राप्तियां – ऐसी प्राप्तियां जिनसे सरकार की आस्ति-देयता की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत करों (जैसे आयकर, कंपनी कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि) से प्राप्तियां और सरकार का गैर कर राजस्व (जैसे ब्याज प्राप्तियां, शुल्क/इस्तेमाल प्रभार और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभांश और लाभ) शामिल है.

सरकारी व्यय का वर्गीकरण

i) पूंजी और राजस्व व्यय

कुल सरकारी व्यय को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है यानी पूंजी व्यय और राजस्व व्यय.

● **पूंजी व्यय** – इसके अंतर्गत सरकार के वे खर्च आते हैं जो उसे आस्तियों में बढ़ोतरी या देयताओं में कमी के लिए करने पड़ते हैं.

– **'आस्तियों में कमी'** संबंधी पूंजी व्यय का उदाहरण: (नए फ्लाईओवर का निर्माण, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए गए ऋण).

– **'देयता में कमी'** संबंधी पूंजी व्यय का उदाहरण: (केंद्र सरकार द्वारा अतीत में दिए गए किसी ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान).

● **राजस्व व्यय** – सरकार के ऐसे व्यय जिनका असर उसकी आस्ति-देयता की स्थिति पर नहीं पड़ता.

राजस्व व्यय के उदाहरण: (खाद्य सब्सिडी, कर्मचारियों के वेतन, औषधियों की खरीद, पाठ्यपुस्तकों की खरीद, ब्याज भुगतान आदि पर किया गया व्यय).

हमें यहां ध्यान देना होगा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों की समस्त राशि केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय के अंतर्गत रिपोर्ट की जाती है, हालांकि राज्यों द्वारा उन अनुदानों का एक हिस्सा स्कूल भवनों, अस्पतालों आदि के निर्माण के लिए किया जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्रीय अनुदानों से निर्मित स्कूल या अस्पतालों का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास नहीं होता. ii) योजना और गैर योजना व्यय

सरकार के कुल व्यय को भी श्रेणियों के अन्य वर्ग में विभाजित किया जा सकता है जैसे योजना व्यय और गैर योजना व्यय.

● **योजना व्यय** – सरकार के ऐसे व्यय जो चालू/पिछली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों/स्कीमों के लिए निर्धारित किए गए हों. जब तक किसी योजना कार्यक्रम की अवधि पूरी नहीं हो जाती (अर्थात जब तक वह किसी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा रहता है), तब तक उस कार्यक्रम पर समस्त व्यय योजना व्यय के अंतर्गत रिपोर्ट किए जाते हैं भले ही वे बुनियादी सुविधाओं के निर्माण या कर्मचारियों के वेतन से सम्बद्ध हों.

योजना कार्यक्रमों की श्रेणियां

● **राज्य योजना कार्यक्रम** – इनके लिए केवल राज्य सरकार धन उपलब्ध कराती है और केंद्र का कोई सीधा योगदान नहीं होता. किंतु, योजना आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करता है.

● **केंद्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम** – इन कार्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार समूची धनराशि उपलब्ध कराती है.

● **केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम** – इन कार्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों धन उपलब्ध कराती हैं. उनके योगदान का अनुपात कार्यक्रम की रूपरेखा पर निर्भर करता है.

● **गैर योजना व्यय** – सरकार के ऐसे खर्च जो योजना आयोग के दायरे से बाहर होते हैं. सभी सरकारी संस्थानों और सेवाओं, जिनका संचालन पंचवर्षीय योजना से इतर नियमित आधार पर किया जाता है, के लिए धन की व्यवस्था गैर योजना व्यय के रूप में की जाती है. इसके उदाहरणों में ब्याज भुगतान, पेंशन, रक्षा व्यय, कानून व्यवस्था पर खर्च, व्यवस्थापिका पर खर्च, सब्सिडीज और नियमित शिक्षकों, डॉक्टरों और अन्य सरकारी कर्मचारियों आदि के वेतन का भुगतान जैसे खर्च शामिल हैं.

यहां हमें इस बात पर अवश्य ध्यान देना है कि विकास संबंधी ज्यादातर क्षेत्र जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता आदि के लिए धन की व्यवस्था योजना और गैर योजना दोनों प्रकार के व्ययों के अंतर्गत की जाती है.

घाटा और ऋण

किसी वर्ष से संबंधित सरकार की आय से अधिक व्यय उस वर्ष के लिए घाटे के रूप में जाना जाता है. सरकार इस घाटे को ऋण लेकर पूरा करती है.

राजकोषीय घाटा: इसका अर्थ है किसी वर्ष के लिए सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच अंतराल (नए ऋण को छोड़ कर). इस प्रकार किसी वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा उस वर्ष लिए गए ऋणों की राशि.

राजस्व घाटा: यह राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतराल है.

बजट अनुमान और संशोधित अनुमान

आने वाले वित्त वर्ष के लिए बजट में प्रस्तुत अनुमान, बजट अनुमान कहलाते हैं, जबकि चालू वित्त वर्ष के लिए वित्त वर्ष की प्रथम छमाही के निष्पादन के आधार पर प्रस्तुत किए गए अनुमान, संशोधित अनुमान कहलाते हैं. पिछले वित्त वर्ष के लिए आंकड़े, जो लेखा परीक्षा के बाद दिए गए हों, वास्तविक कहलाते हैं.

(अगले अंक में जारी रहने की संभावना)

(लेखक नीति अनुसंधान और समर्थन आधारित संगठन, सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी (सीबीजीए), नई दिल्ली में कार्यरत हैं. ई-मेलः happy@cbgaindia.org).

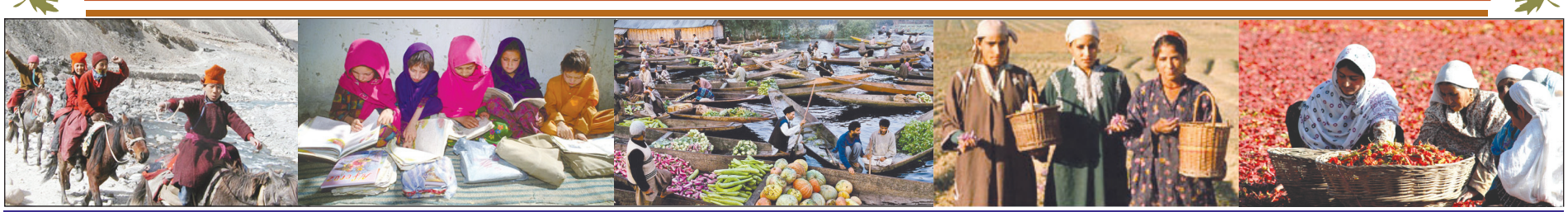

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के लिए ईरा जोशी, अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटिंग प्रेस अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड, सी-21 व 22, सेक्टर-59, नोएडा-201301 में मुद्रित, रोज़गार समाचार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) ईस्ट ब्लाक-IV, लेवल-5, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 द्वारा प्रकाशित, संपादक-डॉ. ममता रानी